शोध पत्र

Feb, 2010

आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक समानता एक चुनौती

* डॉ. सुरेश चन्द्र जैन ** डॉ. महेश कुमार परदेसी

*प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ
** सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ

वर्तमान विश्व परिदृश्य में किसी भी राष्ट्र का विकास उसके मानवीय संसाधनों के बहुमुखी विकास पर निर्भर है, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि

1. समाज में सभी लोगों को अवसरों की समानता प्राप्त हो। 2. उन अवसरों में इतनी स्थिरता हो कि उनका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हो सके । 3. लोगों के पास विकासात्मक प्रक्रिया में भाग लेने व उसका लाभ उठाने का अधिकार हो । मानव विकास की प्रक्रिया समाज के एक भाग विशेष के हितों की रक्षा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सभी वर्गों के लिए अधिकतम विकल्प प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है । जब महिलाओं को इस प्रक्रिया से लाभ उठाने के लिए वंचित कर दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया अन्यायपूर्ण एवं विभेदीकृत हो जाती है । वर्तमान समय में महिलाओं को निरंतर राजनैतिक एवं आर्थिक अवसरों से वंचित किया जा रहा है, जो समाज के आधुनिक विकास की अवधारणा पर अभी भी एक प्रश्नचिन्ह है। बहुत लम्बे समय से यह माना जाता रहा है कि विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया हैं, जिसके लाभ समाज के सभी वर्गो को प्राप्त होंगे तथा इसका प्रभाव लिंग निरपेक्ष होगा, किन्तु प्राप्त अनुभव ठीक इसके विपरीत रहे है ।

इस प्रक्रिया के कारण आज सभी समाजों में यौन असमानता एवं आय विभेदीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यद्यपि स्त्री–पुरूषों के लिए एक समान मानवाधिकार आज विश्वव्यापी स्वीकृत सिद्धान्त है, जिसे विश्व के 171 देशों ने वियना घोषणा–पत्र में हस्ताक्षर करके विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993 में स्वीकार किया है । इस घोषणा–पत्र के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के साथ ही –1. राजनैतिक सहभागिता एवं आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने के संदर्भ में एक समान अवसर, 2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मूलभूत सामाजिक सेवाओं में समानता, 3. समान कार्य के लिए समान वेतन, 4. कानून के अन्तर्गत एक समान सुरक्षा, 5. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं यौन विभेदीकरण का उन्मूलन एवं 6. सार्वजनिक एवं वैयक्तिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकारी होने चाहिए । पुरूषों के साथ–साथ स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की स्वीकृति एवं लैगिंग आधार पर किए जाने वाले विभेदीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की यह भावना गुलामी प्रथा के अंत या साम्राज्यवाद के विनाश जितनी ही महत्वपूर्ण है । किन्तु एक सहज प्रश्न स्वतः उठ खड़ा होता है कि क्या हम उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के बावजूद विश्व परिदृश्य से लैंगिग विभेदीकरण को मिटाने में सफल हुए है?

लैंगिग समानता संबंधी इंडेक्स (GDI - /Gender Related Development Index) के आधार पर विश्व के किसी भी देश में स्त्रियों को पूर्ण समानता नहीं प्राप्त है । विकासशील देशों में तो यह दशा अत्यंत निम्न है । इन देशों में 90 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों में से 60 करोड़ महिलाऐं है (1990) । विकासशील देशों में गर्भ संबंधी जटिलताओं के कारण आज भी लगभग 5.0 लाख महिलायें असमय मृत्यु को प्राप्त करती है। विकासशील देशों में लगभग सभी स्तरों पर यौन असमानता कम करने के प्रयास हो रहे है किन्तु आर्थिक क्षेत्र में अभी भी उनके लिए अवसर कम है । आज विश्व में लगभग 130 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है, इनमें से 70 प्रतिशत महिलाऐं है । महिलाओं में गरीबी का बढ़ना यह प्रदर्शित करता है कि श्रम बाजार एवं परिवार में अभी भी उनकी प्रस्थिति असमान है । महिलाओं का निम्न मूल्यांकन, उनके कार्य को कम करके ऑकने तथा उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान की उपेक्षा में स्पष्ट रूप

से दिखाई देता है । मानव विकास प्रतिवेदन 1995 के अनुसार : ''महिलाएँ लगभग सभी देशों में पुरूषों की अपेक्षा ज्यादा घण्टे तक कार्य करती है । विकासशील देशों में सम्पूर्ण कार्य का लगभग 53 प्रतिशत कार्य एवं विकसित देशों में 51 प्रतिशत कार्य महिलाएँ ही करती है । औसतन स्त्री एवं पुरुष दोनों अपने–अपने सम्पूर्ण कार्य समय का आधा–आधा हिस्सा आय उपार्जन वाले कार्यो, घरेलू कार्यो एवं सामाजिक क्रियाओं में खर्च करते है । किन्तु विकासशील देशों में पुरूष अपने सम्पूर्ण कार्यावधि का तीन चौथाई भाग आर्थिक क्रियाओं में एवं महिलायें इतना ही समय अनार्थिक क्रियाओं में खर्च करती है। परिणामतः पुरूष अपने आर्थिक योगदान की स्वीकृति एवं आय का अधिकतम भाग प्राप्त करता है, जबकि अधिकांश महिला श्रम अभी भी अदृश्य, निम्न मूल्यांकिता एवं अवैतनिक है।

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यो का चूंकि कोई आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाता है, इसलिए महिलाओं के योगदान का निम्न आकलन किया जाता है और उनके कार्यो को यथोचित रूप से पुरस्कृत भी नहीं किया जाता है। महिलाओं के कार्य मूल्यांकन व्यवस्था के असफल रहने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें अन्य आर्थिक विनियमों तथा सम्पत्ति के मालिकाना हक तथा बैंक इत्यादि से ऋण प्राप्त करने से भी वंचित किया गया । समकालीन विश्व में किसी भी व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण उसकी आय–उपार्जन क्षमता पर निर्भर है । इस दृष्टि से महिलाएं अपनी आर्थिक प्रस्थिति के निम्न मूल्यांकन के गम्भीर संकट से गुजर रही है, जबकि सम्पूर्ण कार्य भार का अधिकांश हिस्सा आज भी महिलाओं पर थोपा गया है । किसी भी पुरूष द्वारा बाजार स्थल पर किया जाने वाला कोई भी कार्य उसके अकेले प्रयास का फल नहीं है, अपितु यह उसके ''संयुक्त उत्पादन'' का परिणाम है, जबकि अगर स्त्रियॉ घरेलू कार्यो की जिम्मेदारी लेकर उसे मुक्त न करती तो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य संभव नहीं था । महिलाओं द्वारा किये जाने वाले सम्पूर्ण अवैतनिक कार्यो का यदि यथोचित मूल्यांकन किया जाए तो यह संभव है कि वे अधिकांश समाजों में प्रमुख उपार्जनकर्ता की भूमिका में आ जाए क्योंकि वे पुरूषों की तुलना में लम्बे समय तक कार्य करती है ।

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अव्यवसायिक कार्यो का मौद्रिक मूल्य उनके साथ अन्याय के प्रश्न से कहीं ज्यादा बड़ा है । एक अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में स्त्री–पुरूषों द्वारा किए जाने वाले समस्त अवैतनिक –वैतनिक कार्यो का मूल्य लगभग 160 करोड़ डालर है जिसमें से 100 करोड़ डालर का कार्य महिलाओं द्वारा अकेले, अवैतनिक एवं अदृश्य योगदान के रूप में किया जाता है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय सांख्यिकी महिलाओं के अदृश्य योगदान की पूरी तरह प्रतिबिम्बित करने में सफल रही तो फिर राष्ट्रीय निर्णयों में उनकी उपेक्षा असंभव हो जाएगी और न ही बाजार विनिमय में उन्हें आर्थिक रूप से अवांछित समझा जावेगा। समकालीन विश्व के लगभग सभी देशों में नवीन आर्थिक शक्तियों के उदय, आधुनिक पूंजीवाद के विकास में तीव्र आर्थिक विकास के मॉडल अपनाये जाने तथा ''न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ'' की नव प्रबंधकीय मान्यताओं के कारण स्त्री–पुरूष के परम्परागत यौन आधारित विभेदों में भी परिवर्तन आए है । तृतीय विश्व के संदर्भ में मारिया का मत है कि ''पूंजीवादी बाजार व्यवस्था के कारण महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ अपितु उसके ठीक विपरीत जीवन यापन के अवसरों में भी सभी जगह कमी आई है । विशेष तौर पर गरीब एवं ग्रामीण सीमांत उत्पादकों की स्थिति तो और भी निम्न हुई है । इस गिरावट का मुख्य कारण ''पूंजीवाद पिछड़ापन'' या ''सामंतवादी व्यवस्था'' नहीं है, अपितु यह पूंजीवादी अधुनिकीकरण का एक अनिवार्य प्रभाव है ।''

अतः यह सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रोजगार एवं आय से संबंधित महिलाओं पर कार्यो का बोझ बढ़ा है जबकि तुलनात्मक रूप से उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक प्रस्थिति में गिरावट आई है । रोजगार के क्षेत्र में उनकी प्रस्थिति में आई गिरावट को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्हें मुख्य धारा से काट करके हाशिए पर रख जा रहा है, जिसे हम सीमान्तीकरण भी कह सकते है । इस असमानता का निराकरण करना वर्तमान काल में एक चुनौती है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. United Nations , 1995 , Human Development Report Op. Cit., P. 1.2. United Nations , 1995 , Human Development Report Op. Cit., P. 4. 3. United Nations , 1995 , Human Development Report Op. Cit., P. 6. 4. Miers Maria , 1988 , Introduction in Mies, Bennhold Thomson and Von Wealhof Women The Last Colony New Delhi. 5. United Nations , 1993 , The Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights, Vienna. 6. HDI & GDI , The Human Development Index.